

प्रेषक,

राधा रत्नाली,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 23 अप्रैल 2015

विषय:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई एवं जून 2015 महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पेट्रोलियम प्लानिंग एवं एनालिसिस सैल, भारत सरकार के पत्र सं-4198/एस0के0ओ0/2015, दिनांक-01.04.2015 एवं राज्य स्तरीय समन्वयक-तेल उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं-डी0डी0एन0डी0ओ0/एम0/24, दिनांक-03.04.2015 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, शासनादेश सं-जी0 आई0-41/29-7-53 (के0ओ0) दिनांक 09 जुलाई, 1990 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए वर्ष 2015-16 के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई एवं जून 2015 हेतु जनपदवार/कम्पनीवार/थोक मिट्टी तेल विकेतावार उपभोक्ताओं को मासिक आवंटन सलग्नक-1, 2 एवं 3 में उल्लिखित मात्रानुसार कुल 2912 के0एल0 मासिक मिट्टी तेल का आवंटन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रत्येक जनपद के सम्मुख स्टैण्डर्ड आवंटन के अन्तर्गत जो मात्रा दी जा रही है वह केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दुकानदारों के माध्यम से राशन कार्ड पर निर्धारित दर में नियमानुसार वितरित की जायेगी। इस मात्रा को किसी भी स्थिति में किसी अन्य प्रयोजनों में नहीं लाया जायेगा।

2. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए जहां कही आवश्यकता हो एक स्पेशल कोटे के तहत छात्रों/छात्रवासों, शिक्षण संस्थाओं, विवाह, अन्योष्टि, ईट भट्ठे में कार्यरत मजदूरों तथा सरकारी उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार आवंटन किया जायेगा जिसकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा शासन को उपलब्ध करानी होगी।

3. जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा "श्री स्टेज वैकिंग" करायी जायेगी। किसी भी दशा में मिट्टी तेल का डाइवर्जन/अपमिश्रण न हो, जिसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।

4. मिट्टी तेल का शतप्रतिशत सही वितरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी (सिंगल बॉटल) राशनकार्ड धारकों को भारत सरकार से, मिट्टी तेल का कम आवंटन प्राप्त होने के दृष्टिगत मिट्टी तेल अनुमन्य नहीं किया जायेगा। बिना एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को 05 लीटर प्रति राशन कार्ड मैदानी क्षेत्र में तथा 07 लीटर, प्रति राशन कार्ड पर्वतीय जनपदों में मिट्टी तेल वितरित किया जायेगा। डी0बी0सी0 कनेक्शनधारी के राशनकार्डों पर मिट्टी का तेल अनुमन्य नहीं होगा।

5. जिलाधिकारी अपने जनपद में मिट्टी तेल की मांग/उपलब्धता/आपूर्ति को देखते हुये व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखेंगे।

6. उपरोक्तानुसार आवंटन के पश्चात् वर्तमान त्रैमास हेतु कुल 60 के0एल0 मिट्टी तेल आई0ओ0सी0 का रिजर्व में अवशेष रहेगा।

7. एजेंसीवार वितरण में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होने की दशा में जिलाधिकारी अपना प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित तत्काल शासन को उपलब्ध कराएं ताकि आगामी माहों में तदनुसार परिवर्तन किया जा सकें।

8. प्रथम त्रैमास हेतु माह अप्रैल, 2015 हेतु आवंटित मिट्टी तेल का उठान/वितरण दिनांक—05.05.2015 तक तथा मई एवं जून 2015 हेतु आवंटित मिट्टी तेल का उठान/वितरण उसी माह की अन्तिम तिथि तक प्रत्येक दशा में कर लिया जाय।

9. आवंटित की गई मात्रा के मिट्टी तेल को इसी माह में उठान के लिए तत्काल एजेन्सी/डीलर को निर्देश जारी कर दिये जायें। आवंटित तेल की मात्रा का साथ उठान सुनिश्चित कराया जाय।

10. उल्लेखनीय है कि, भारत सरकार द्वारा, प्रत्येक त्रैमास हेतु, उत्तराखण्ड राज्य, को आवंटित मिट्टी तेल के कोटे की मात्रा में निरन्तर कटौती की जा रही है। इसके दृष्टिगत, किन्हीं एजेन्सियों द्वारा उठान न किये जाने की स्थिति में, जिला पूर्ति अधिकारी अपने स्तर से, अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि, ऐसी कितनी एजेन्सियां हैं, जो 03 माह हेतु आवंटित कोटे का कतिपय कारणों से पूर्ण/आंशिक उठान नहीं कर पा रही हैं, साथ ही इसकी सूचना प्रत्येक जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में त्रैमास समाप्त होने से पूर्व शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीया,

(राधा रत्नाली)

प्रमुख सचिव।

संख्या—915 (1) / XIX-1 / 15-मि0तोआवं-112 / 2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उप सचिव, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढवाल/कुमाऊ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
5. राज्य स्तरीय समन्वयक उत्तराखण्ड, आई०आ०सी० देहरादून/बरेली को जनपदवार/एजेंसीवार/थोक विक्रेतावार मिट्टी तेल के आवंटन के प्रति संलग्न करते हुये इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित तेल डिपो तथा सम्बन्धित तेल कम्पनी को आवंटन के अनुसार मिट्टी तेल उपलब्ध कराने का निर्देश करना सुनिश्चित करें।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच०पी०सी०एल०, 94 गोविन्दनगर रेसकोर्स, देहरादून।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, बी०पी०सी०एल०, 05 फ्लोर 04 एवं 06 लक्सर रोड, रुड़की, हरिद्वार।
8. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रमुख निजी सचिव, मा० खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
10. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
11. समन्वयक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड, सचिवालय देहरादून।
12. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनंद सिंह बोरा)

अनु सचिव।